SLCM GROUP IN NEWS: KISSANDHAN

Publication	Date	Online Edition	Article
Kisan Tak (India Today)	Jan 27, 2025	Worldwide	Read More

किसान Tak होम मंडी भाव खबरें सरकारी स्कीम मंडी रेट्स वेब स्टोरी सक्सेस स्टोरी टिप्स और ट्रिक्स

News / खाद बीज / Budget 2025: टिकाऊ खेती के लिए नई नीतियां लाए सरकार, IIL के एमडी बोले- एग्री केमिकल सेक्टर को राहत की जरूरत

किसान तक के चैनल से जुड़ें

Budget 2025: टिकाऊ खेती के लिए नई नीतियां लाए सरकार, IIL के एमडी बोले- एग्री केमिकल सेक्टर को राहत की जरूरत

कृषि सेक्टर की कंपनियों के उच्चाधिकारियों ने बजट 2025-26 में कृषि के लिए कई बड़ी घोषणाओं और बदलावों की उम्मीद जताई है. इनमें किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने से लेकर केमिकल इनपुट पर जीएसटी कटौती के साथ ही प्राकृतिक खेती और डिजिटल सॉल्यूशन पर नई नीतियां और एसओपी लाने की मांग की है.

ADVERTISEMENT
A PERFECT FIT
msc Export your Retail with MSC Sign Up

एक्सपर्ट ने कहा केंद्रीय बजट में कृषि का भविष्य इनोवेशन, वित्तीय समावेशन पर केंद्रित होना चाहिए.

कृषि के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार जरूरी - संदीप सभरवाल

अनाज स्टोरेज समेत किसानों को कमोडिटी पर वित्तीय सुविधा देने वाली कंपनी सोहन लाल कमोडिटी मैनेजमेंट (SLCM) लिमिटेड के ग्रुप सीईओ संदीप सभरवाल ने कहा कि केंद्रीय बजट 2025 पर कृषि का भविष्य इनोवेशन, वित्तीय लचीलेपन पर केंद्रित होना चाहिए. छोटे और सीमांत वर्ग के किसानों के सामने आने वाली चुनौतियों के लिए अभी भी केंद्रित नीतिगत हस्तक्षेप की जरूरत है. सबसे पहले कृषि के लिए डिजिटल सार्वजनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार करने की तत्काल जरूरत है. एग्रीस्टैक जैसी पहलों की सफलता ने किसानों को महत्वपूर्ण सेवाओं तक पहुंच बनाने में सक्षम बनाने में मदद की है.

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने की जरूरत भी है. यह बदलाव किसानों को इनपुट लागत और अप्रत्याशित खर्चों को मैनेज करने के लिए जरूरी लिक्विडिटी की सुविधा देगा. खासकर बुवाई और कटाई की अवधि के दौरान. उन्होंने कहा कि सरकार की मौजूदा ब्याज छूट और रिपेमेंट प्रोत्साहनों के साथ, क्रेडिट लिमिट बढ़ाने से किसानों की किफायती लोन तक पहुंच बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी, जिससे उन्हें खर्च और आय के बीच के अंतर को पाटने में मदद मिलेगी.

हम कृषि अनुसंधान और विकास में निवेश को कृषि-जीडीपी के कम से कम 1 फीसदी तक बढ़ाने की भी उम्मीद करते हैं, जो न केवल सप्लाई चेन को बढ़ाने और कटाई के बाद फसल प्रबंधन के एसओपी को व्यवस्थित करने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का निर्माण कर सकता है, बल्कि खाद्य अपशिष्ट को कम करने, किसानों की आय में सुधार करने और खाद्य सुरक्षा पक्की करने में भी मदद कर सकता है.